Q.1) नीति आयोग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया है।
2. इसका एक उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.1) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
नीति आयोग, भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प (अर्थात, केंद्रीय मंत्रिमंडल) द्वारा स्थापित एक निकाय है। इसलिए, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है।	नीति आयोग के उद्देश्य में शामिल हैं- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना तथा सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर रूप से व्यवस्थित करना।

Q.2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं।
2. आयोग का अध्यक्ष, भारत का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
3. सदस्यों में, तीन व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) को मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	**असत्य**	**सत्य**
आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं।	अध्यक्ष को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।	सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए तथा तीन व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) को मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

Q.3) निम्नलिखित आयोगों में से किसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पदेन सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं?

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
4. राष्ट्रीय महिला आयोग

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1,2 और 4
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.3) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सात पदेन सदस्य होते हैं - निम्न आयोग के अध्यक्ष

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
- राष्ट्रीय महिला आयोग,
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

Q.4) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए या जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
2. अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।	अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

Q.5) राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एक SHRC केवल संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
2. केंद्र सरकार, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों को SHRCs को दे सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**असत्य**
राज्य मानवाधिकार आयोग केवल **संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची- II) और समवर्ती सूची (सूची- III)** में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।	केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोगों को दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों के मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों को दे सकती है। **दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** द्वारा निपटाया जाना है।

Q.6) केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. राज्य के विधानमंडल के सदस्य को सीआईसी में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को हटाते समय सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**असत्य**
आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम दस सूचना आयुक्त (वर्तमान में 6) होते हैं। उन्हें कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का	राष्ट्रपति दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। हालाँकि, इन मामलों में, राष्ट्रपति को इस मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय, जांच के बाद, हटाने के कारण को बताता है और सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं।

सदस्य नहीं होना चाहिए।	

Q.7) निम्नलिखित में से कौन से निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं?

1. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council)
2. आंचलिक परिषद (Zonal Councils)
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. राष्ट्रीय जांच एजेंसी

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1,2 और 4
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.7) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निकाय निम्न हैं:

- अंतर-राज्य परिषद
- आंचलिक परिषद
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Q.8) राज्य सूचना आयोग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य सूचना आयुक्त ऐसे पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
2. राज्यपाल के पास राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्तियां होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और एक राज्य सूचना आयुक्त ऐसे पद के लिए **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करते, जो भी पहले	राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को कार्यालय से हटा सकता है:

हो, के लिए पद धारण करते हैं।	(a) यदि उसे दिवालिया माना जाता है; या (b) यदि उसे अपराध का दोषी ठहराया गया है (राज्यपाल की राय में) इसमें नैतिक भ्रष्टता शामिल है; या (c) यदि वह अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान संलग्न है; या (d) यदि वह (राज्यपाल की राय में) मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या (e) यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित का अधिग्रहण किया है, जिससे कि उसके आधिकारिक कार्यों को पूर्वाग्रह से प्रभावित करने की संभावना है। इनके अतिरिक्त, राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। हालाँकि, इन मामलों में, राज्यपाल को मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना पड़ता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय, जांच के बाद, हटाने के कारण को बताता है और सलाह देता है, तो राज्यपाल उसे हटा सकते हैं।

Q.9) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. CVC की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।
2. इसकी स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी। इस प्रकार, मूल रूप से CVC न तो संवैधानिक निकाय था और न ही वैधानिक निकाय। बाद में, 2003 में, संसद ने सीवीसी पर वैधानिक दर्जा देने वाला विधान अधिनियमित बनाया।	इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा (1962-64) द्वारा की गई थी।

Q.10) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. केंद्र सरकार को केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून बनाने में सीवीसी से परामर्श करने की आवश्यकता होती है।
2. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत संदिग्ध लेनदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए CVC को एक विशिष्ट प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
केंद्र सरकार को केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून बनाने में सीवीसी से परामर्श करने की आवश्यकता होती है।	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत संदिग्ध लेनदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक विशिष्ट प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

Q.11) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों, आतंक से संबंधित अपराधों तथा गंभीर और संगठित अपराध की जांच करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**असत्य**
CBI की स्थापना की भ्रष्टाचार पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा संस्तुति की गई थी। इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बाद में, इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था तथा अब इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी	राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और CBI द्वारा जांच किए गए मामलों की प्रकृति में अंतर है। एनआईए का गठन मुख्य रूप से आतंकवादी हमलों, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य आतंकवादी संबंधित अपराधों की घटनाओं की जांच के लिए 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद किया गया है, जबकि सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और आतंकवाद के अलावा गंभीर और संगठित

शक्तियों को प्राप्त करता है।	अपराध की जांच करती है।

Q.12) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) के तहत, भारत में लोकपाल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वे संस्थाएँ जो सरकार द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्तपोषित और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान हैं, लोकपाल के प्राधिकार क्षेत्र में आते हैं।
2. लोकपाल को लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई पर अधीक्षण और निर्देश की शक्ति है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थानों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को बाहर रखा गया है।	लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए लोकपाल के पास सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देश की शक्ति होगी।

Q.13) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) के तहत, भारत में लोकपाल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतःसंज्ञान (suo motu) कार्यवाही नहीं कर सकता है।
2. लोकपाल के पास शिकायतें दर्ज करने के लिए 7 वर्ष की सीमा अवधि होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.13) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतःसंज्ञान (suo motu) कार्यवाही नहीं कर सकता है।	लोकपाल के समक्ष शिकायतें दर्ज करने के लिए 7 वर्ष की सीमा अवधि होती है।

Q.14) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में हुई थी।

2. एनआईए का क्षेत्राधिकार आतंकी हमलों, साइबर आतंकवाद, जाली नोटों और मानव तस्करी तक विस्तारित है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.14) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
एनआईए को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया था, जिसे 26/11 की घटना के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) के प्रावधानों के तहत किया गया था। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।	एनआईए को बम विस्फोटों, हवाई जहाजों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करने का अधिकार है। 2019 में, एनआईए के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित किया गया था। परिणाम स्वरूप, एनआईए को मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराधों की जांच करने, निषिद्ध हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर-आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों की बिक्री की जाँच करने का भी अधिकार है।

Q.15) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
2. गृह मंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
3. एनडीएमए के कार्यों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना शामिल है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
एनडीएमए केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।	**प्रधान मंत्री** एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है।	एनडीएमए के कार्यों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना शामिल है।

Q.16) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जिले का कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है।
2. जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीडीएमए के पदेन सदस्यों में से एक हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
एक डीडीएमए में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन सात से अधिक नहीं। जिले का कलेक्टर (या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त) डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है।	डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीडीएमए के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम दो जिला स्तरीय अधिकारियों को डीडीएमए के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

Q.17) भारत में सहकारी समितियों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
2. एक शीर्ष सहकारी समिति के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधायिका के समक्ष रखी जाती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
2011 के 97 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इस संदर्भ में, इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए: 1. इसने सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)। 2. इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर एक नया राज्य नीति का निर्देश सिद्धांत शामिल किया (अनुच्छेद 43-B)। 3. इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा, जिसका शीर्षक "सहकारी समितियां" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) हैं।	वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह महीने के भीतर प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का ऑडिट किया जाएगा। एक शीर्ष सहकारी समिति के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधायिका के समक्ष रखी जाएगी।

Q.18) संविधान के तहत दिए गए संघ और राज्यों की संपत्ति के बारे में, निम्नलिखित पर विचार करें

1. संघ या राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति के अभ्यास के तहत संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान कर सकते हैं।
2. राज्यों के पास प्रादेशिक जल (territorial waters) में मौजूद खनिजों पर अधिकार होता है जबकि महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र में खनिजों के मामले में, केवल संघ का अधिकार होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**असत्य**
अनुच्छेद 298 के अनुसार, संघ या एक राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति के अभ्यास के तहत संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान कर सकता है।	भारत के समुद्री जल (प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र) के अंतर्गत सभी भूमि, खनिज और मूल्य की अन्य चीजें, **संघ में निहित है।** इसलिए, समुद्र क्षेत्र में एक राज्य इन चीजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता है।

Q.19) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान में उन जातियों या जनजातियों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति कहा जाता है।
2. संविधान ने उन व्यक्तियों को परिभाषित किया है जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
संविधान उन जातियों या जनजातियों को निर्दिष्ट नहीं करता है जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति कहा जाता है। यह राष्ट्रपति को यह निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में माना जाए।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के मामले के विपरीत, संविधान ने उन व्यक्तियों को परिभाषित किया है जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से हैं। तदनुसार, 'एंग्लो-इंडियन का अर्थ, एक व्यक्ति जिसका पिता या पुरुष लाइन में कोई अन्य पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश का है या जो भारत के क्षेत्र के भीतर अधिवासित है और माता-पिता एक ऐसे क्षेत्र के भीतर पैदा हुए थे, जहाँ

	सामान्य निवासी थे और केवल अस्थायी उद्देश्यों के लिए वहां स्थापित नहीं किए गए थे' हैं।

Q.20) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के बारे, में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. CAT, भर्ती और इसके द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के सभी सेवा संबंधी मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र (original jurisdiction) का उपयोग करता है।
2. CAT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
CAT भर्ती और उसके द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक विस्तारित है। हालांकि, रक्षा बलों के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके अंतर्गत नहीं हैं।	CAT 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। ये सिद्धांत CAT को दृष्टिकोण में लचीला रखते हैं।

Q.21) नारी शक्ति पुरस्कारों (Nari Shakti Puruskar) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है / हैं?

1. रानी रुद्रम्मा देवी पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ पंचायत / ग्राम समुदाय
2. देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार - महिलाओं को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय।
3. माता जीजाबाई पुरस्कार - बाल लिंग अनुपात (CSR) में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य।
4. रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार - महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 4
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1, 2 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.21) Solution (a)

- वर्ष 2016 से, प्रत्येक वर्ष 20 नारी शक्ति पुरुस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

- यह पुरस्कार उन संस्थानों और व्यक्तियों पर लागू होगा, जिन्होंने विशेष रूप से समाज के कमजोर और हाशिए के तबके से जुड़ी महिलाओं के कारण प्रतिष्ठित सेवाएं प्रदान की हैं।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है क्योंकि यह महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल मंत्रालय है।
- पुरुस्कारों के प्राप्तकर्ता को प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को घोषित किया जाएगा तथा पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।
- पुरुस्कारों को मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।

पुरस्कारों की श्रेणी इस प्रकार होगी:

- सर्वश्रेष्ठ पंचायत / ग्राम समुदाय के लिए रानी रुद्रम्मा देवी पुरस्कार जिन्होंने महिला कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है
- महिलाओं को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय को माता जीजाबाई पुरस्कार दिया जायेगा।
- सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए कन्नगी देवी पुरस्कार जिसने बाल लिंग अनुपात (CSR) में काफी सुधार किया है।
- रानी गाइदिन्ल्यू ज़ेलियांग पुरुस्कार सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज संगठन (CSO) को महिलाओं के कल्याण और भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जायेगा।
- देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरुस्कार महिलाओं की भलाई और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रदान किया जायेगा।
- रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान को प्रदान किया जायेगा।

Q.22) ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड (Operation Spring Shield) किसके द्वारा एक सीमा पार सैन्य अभियान था

a) तुर्की सशस्त्र बलों के विरुद्ध रूसी सशस्त्र बलों का
b) सीरियाई सशस्त्र बलों के विरुद्ध तुर्की सशस्त्र बलों का
c) यमन सशस्त्र बलों के विरुद्ध सऊदी अरब सशस्त्र बलों का
d) सीरियाई सशस्त्र बलों के विरुद्ध रूसी सशस्त्र बलों का

Q.22) Solution (b)

- ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड एक सीमा-पारीय सैन्य अभियान था, जो तुर्की सशस्त्र बलों द्वारा उत्तर-पश्चिम सीरिया के इदलिब जिले में सीरियाई सशस्त्र बलों के विरुद्ध किया गया था।
- 27 फरवरी 2020 को इदलिब में तुर्की सशस्त्र बल (TSK) द्वारा सीमा पार सैन्य अभियान आरंभ किया गया था।
- यह अभियान बाल्यन हमले के प्रतिउत्तर में आरंभ किया गया था।
- तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन का उद्देश्य अस्ताना फ्रेमवर्क के अंतर्गत था, ताकि सोची में युद्ध विराम समझौता सुनिश्चित हो सके और इदलिब से तुर्की सीमा की ओर प्रवास को रोका जा सके।
- 5 मार्च को तुर्की और रूस ने मास्को में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

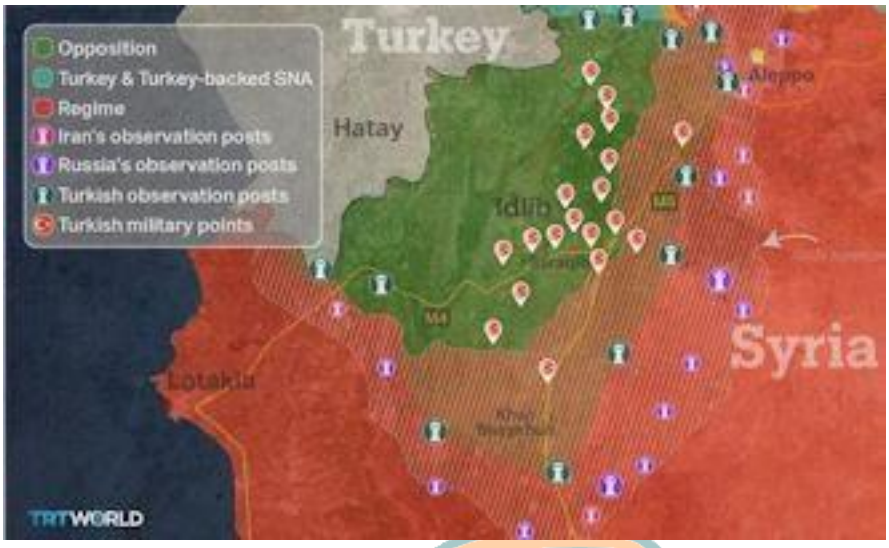

Q.23) अतिरिक्त टियर -1 बॉन्ड (Additional Tier-1 Bonds) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. AT-1 बॉन्ड के धारक अपने निवेश को द्वितीयक ऋण बाजार में बेचकर वापस प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि जारीकर्ता उन्हें प्रतिदेय (redeems) नहीं करता।
2. इन बॉन्डों पर ब्याज केवल जारी करने वाले निकाय के विवेकाधिकार पर चुकाया जा सकता है और वह भी वार्षिक लाभ से बाहर होता है।
3. यदि आरबीआई को लगता है कि कोई बैंक लड़खड़ाने की कगार पर है तथा उसे बचाव की जरूरत है, तो वह इसके निवेशकों से सलाह लिए बिना बैंक से बकाया AT -1 बांड रद्द करने के लिए कह सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

a) केवल 1 और 3
b) केवल 3
c) केवल 2 और 3
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.23) Solution (d)

- भारत में, बैंकों को अपने जोखिम-भारित ऋण के 11.5 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात में पूंजी बनाए रखना चाहिए। इसमें से 9.5 फीसदी टियर -1 की पूंजी में और 2 फीसदी टियर -2 में होना चाहिए।
- टियर -1 पूंजी इक्विटी और स्थायी पूंजी के अन्य रूपों को संदर्भित करती है जो बैंक के साथ रहती है, क्योंकि जमा और ऋण प्रवाह के माध्यम से अंदर और बाहर होती हैं।
- AT-1 बॉन्ड वार्षिक कूपन धारक बॉन्ड होते हैं जिनकी कोई निश्चित परिपक्वता तिथि नहीं होती है। इन बॉन्डों पर ब्याज दर निश्चित जमा दरों से अधिक होती है, जो उन्हें आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है।
- इन बॉन्ड के धारक अपने ऋण को द्वितीयक ऋण बाजार में बेचकर वापस प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि जारीकर्ता उन्हें प्रतिदेय (redeems) नहीं करता।
- इन बांडों को जारी करने वाले के पास इनके प्रतिदेय (redeems) के लिए कानूनी दायित्व नहीं होता हैं। इन बॉन्डों पर ब्याज केवल जारी करने वाले निकाय के विवेकाधिकार पर चुकाया जा सकता है और वह भी वार्षिक लाभ से बाहर होता है।

AT -1 बांड की असामान्य विशेषताएं (Unusual features of AT-1 bonds)

- ये बांड्स स्थायी होते हैं और कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है। इसके बजाय, वे कॉल ऑप्शन (call options) लिए होते हैं जो बैंकों को पांच या 10 साल बाद उन्हें प्रतिदेय करने की अनुमति देते हैं। लेकिन बैंक इस कॉल ऑप्शन का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं तथा अनंत काल के लिए इन बांडों पर केवल ब्याज का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- AT -1 बांड जारी करने वाले बैंक किसी विशेष वर्ष के लिए ब्याज भुगतान को देने से मना कर (skip) सकते हैं या यहां तक कि बांड के अंकित मूल्य को कम कर सकते हैं।
- अगर आरबीआई को लगता है कि कोई बैंक लड़खड़ाने की कगार पर है और उसे बचाव की जरूरत है, तो वह अपने निवेशकों से सलाह लिए बिना बैंक से बकाया AT -1 बांड रद्द करने के लिए कह सकता है।

AT -1 बॉन्ड प्रति बॉन्ड पर 10 लाख रूपए का मूल्य रखता है। ऐसे दो मार्ग हैं जिनके माध्यम से खुदरा लोगों ने इन बॉन्डों का अधिग्रहण किया है - बैंकों द्वारा AT -1 बॉन्ड्स के शुरुआती निजी प्लेसमेंट ऑफर जो धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं; या द्वितीयक बाजार ब्रोकर्स की सिफारिशों के आधार पर पहले से ही कारोबार किए गए AT -1 बांड की खरीद करता है।

Q.24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्टॉक स्वैप (Stock swap) एक विलय या अधिग्रहण की परिस्थितियों से संबद्ध दूसरे के लिए एक इक्विटी-आधारित संपत्ति का आदान-प्रदान है।
2. स्टॉक स्वैप तब होता है जब लक्ष्यित कंपनी के शेयरों के स्वामित्व वाले शेयरधारकों का अधिग्रहण कंपनी के शेयरों के लिए किया जाता है।
3. स्वैप अनुपात (Swap ratio) वह अनुपात है जिस पर एक अधिग्रहण करने वाली कंपनी एक विलय या अधिग्रहण के दौरान लक्ष्यित कंपनी के शेयरों के बदले में अपने स्वयं के शेयरों को प्रस्तुत करेगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.24) Solution (d)

- स्टॉक स्वैप (Stock swap) एक विलय या अधिग्रहण की परिस्थितियों से संबद्ध दूसरे के लिए एक इक्विटी-आधारित संपत्ति का आदान-प्रदान है।
- स्टॉक स्वैप तब होता है जब लक्ष्यित कंपनी के शेयरों के स्वामित्व वाले शेयरधारकों का अधिग्रहण कंपनी के शेयरों के लिए किया जाता है।
- स्वैप अनुपात (Swap ratio) वह अनुपात है जिस पर एक अधिग्रहण करने वाली कंपनी एक विलय या अधिग्रहण के दौरान लक्ष्यित कंपनी के शेयरों के बदले में अपने स्वयं के शेयरों को प्रस्तुत करेगी।
- स्वैप अनुपात की गणना करने के लिए, कंपनियां वित्तीय अनुपात जैसे कि बुक वैल्यू, प्रति शेयर आय, कर के बाद लाभ, और लाभांश भुगतान का विश्लेषण करती हैं।
- एक स्वैप अनुपात एक लक्ष्य कंपनी के शेयरधारकों को बताता है कि वर्तमान में उनके पास लक्षित कंपनी के शेयर के प्रत्येक एक शेयर के लिए उन्हें प्राप्त कंपनी के कितने शेयर प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक अधिग्रहण करने वाली कंपनी 1.5: 1 का स्वैप अनुपात प्रदान करती है, तो वह लक्ष्य कंपनी के प्रत्येक 1 शेयर के लिए अपनी कंपनी के 1.5 शेयर प्रदान करेगा। लक्ष्य कंपनी का एक शेयरधारक पहले की तुलना में 50% अधिक शेयरों के साथ समाप्त होगा, लेकिन उनके नए शेयर अधिग्रहण करने वाली कंपनी के लिए होंगे और अधिग्रहण करने वाली कंपनी की कीमत होगी। लक्ष्य कंपनी के शेयरों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है।

Q.25) त्रिपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास "समुद्री सुरक्षा बेल्ट" (Marine Security Belt) निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों के बीच आयोजित किया गया था?

a) संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और थाईलैंड
b) ईरान, रूस और चीन
c) भारत, मलेशिया और थाईलैंड
d) ईरान, इराक और सऊदी अरब

Q.25) Solution (b)

- यह दो प्रमुख विश्व शक्तियों रूस और चीन के साथ ईरान का त्रिपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था।
- ईरान, रूस और चीन द्वारा चार-दिवसीय संयुक्त समुद्री ड्रिल को **"समुद्री सुरक्षा बेल्ट" (Marine Security Belt)** नाम दिया गया है, जिसमें हमले के तहत बचाव के तौर पर सामरिक अभ्यास शामिल हैं।
- यह दक्षिणपूर्वी ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार में आरंभ हुआ तथा हिंद महासागर के उत्तरी हिस्सों में जारी है।
- ओमान सागर एक विशेष रूप से संवेदनशील जलमार्ग है क्योंकि यह होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ता है, जिसके माध्यम से विश्व का लगभग 30% कच्चा तेल गुजरता है और जो फारस की खाड़ी से जुड़ता है।
- इस अभ्यास का संदेश सहयोग और एकता के माध्यम से शांति, मित्रता और स्थायी सुरक्षा है

Q.26) 'अविश्वास प्रस्ताव' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत विशेष रूप से किया गया है।
2. जे.बी. कृपलानी ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 1971 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26) Solution (d)

संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इस तरह के प्रस्ताव को संसदीय नियम प्रक्रिया के नियम 198 के तहत स्थानांतरित किया जाता है।

जे.बी. कृपलानी ने भारत-चीन युद्ध के पश्चात् नेहरू सरकार के विरुद्ध अगस्त 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया था।

Q.27) 'सेसा आर्किड अभयारण्य' (Sessa Orchid Sanctuary) कहाँ स्थित है

a) कर्नाटक
b) अरुणाचल प्रदेश
c) उत्तराखंड
d) सिक्किम

Q.27) Solution (b)

सेसा ऑर्किड अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।

Q.28) निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी से होकर बहती है?

1. डेन्यूब
2. ओडर
3. एल्ब

सही कूट का चयन करें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.28) Solution (d)

डेन्यूब-ओडर-एल्ब नहर

- डेन्यूब-ओडर-एल्ब नहर का आशय डेन्यूब, ओडर और एल्ब नदियों को जोड़ने का है तथा इस प्रकार काला सागर से उत्तरी और बाल्टिक सागर के लिए एक और नौगम्य लिंक प्रदान करता है।

डेन्यूब

- वोल्गा के बाद यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- यह मध्य और पूर्वी यूरोप में स्थित है।
- जर्मनी में उत्पन्न, डेन्यूब 2,850 किमी के लिए दक्षिण-पूर्व में बहती है, काले सागर में मिलने से पहले ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से गुजरती है।

एल्ब

- यह मध्य यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है।
- यह बोहेमिया (चेक गणराज्य के पश्चिमी भाग) के बहुत अधिक क्षेत्र कवर करने से पहले उत्तरी चेक गणराज्य के क्रैकोनोसे पर्वत से निकलती है, फिर जर्मनी और हैम्बर्ग से 110 किमी उत्तर-पश्चिम में बहते हुए Cuxhaven में उत्तरी सागर में मिलती है।

ओडर

- यह मध्य यूरोप और पोलैंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो विस्तुला और वर्ता के बाद है।
- यह चेक गणराज्य में निकलती है और पश्चिमी पोलैंड के माध्यम से 742 किलोमीटर तक बहती है, बाद में पोलैंड और जर्मनी के बीच 187 किलोमीटर की सीमा का निर्माण ओडर-नीइस लाइन के हिस्से के रूप में होता है।

Q.29) 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (International Security Assistance Force- ISAF)' हाल ही में, किससे संबंधित समाचारों में थी?

a) NATO
b) SCO
c) OIC
d) IMCTC

Q.29) Solution (a)

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) अफगानिस्तान में एक नाटो के नेतृत्व वाला सैन्य मिशन था, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दिसंबर 2001 में संकल्प 1386 द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे बॉन समझौते द्वारा परिकल्पित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों (ANSF) को प्रशिक्षित करना और प्रमुख सरकारी संस्थानों के पुनर्निर्माण में अफगानिस्तान की सहायता करना था, साथ ही, ये तालिबान विद्रोह के खिलाफ अफगानिस्तान में युद्ध (2001-14) में भी लगे हुए थे।

Q.30) 'आर-रिनम' (Arr-Rinam) शब्द हाल ही में समाचारों में था तथा यह निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है?

a) गालो समुदाय
b) धनगर समुदाय
c) मिशमी समुदाय
d) सेंटीनली समुदाय / जनजाति

Q.30) Solution (a)

आर-रिनम (Arr-Rinam) 48 घंटे के लिए सर्वसम्मति से लगाए गए लॉकडाउन का गालो समकक्ष (Galo equivalent) है जब भी कोई महामारी आती है। पूर्वी सियांग और लोअर दिबांग घाटी जिलों में बसे आदि समुदाय (Adi community) ने भी मोटर (Motor) नामक एक समान अनुष्ठान किया।